

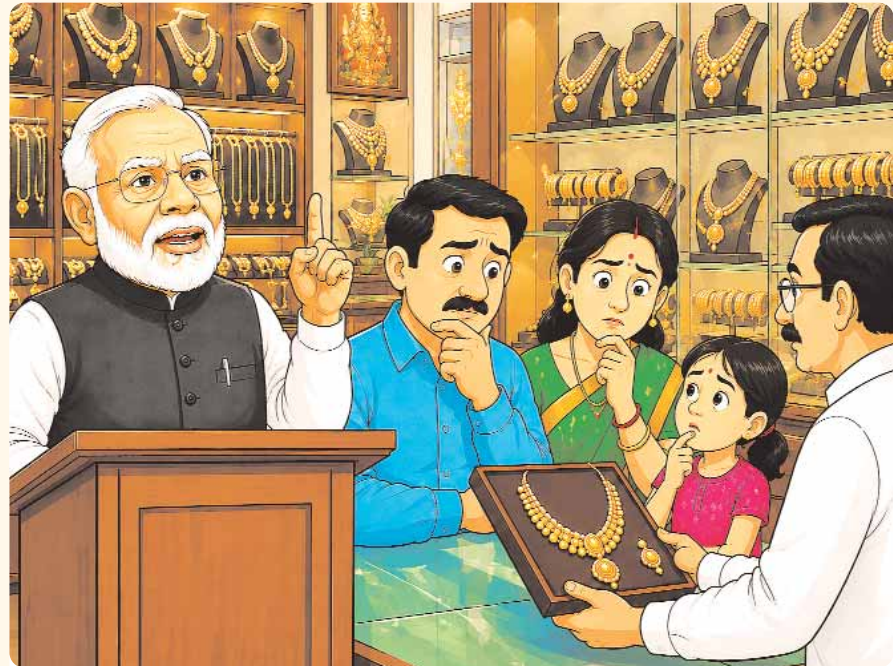
‘सोना’ कितना सोणा है...

कर्म खर्च, बचत ज्यादा, देश की तरक्की का वादा...

महंगा होता तेल और सोना, कमजोर पड़ता रुपया और बढ़ता आयात बिल...इन चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नया आर्थिक मंत्र दिया है ‘कर्म खर्च करें, ज्यादा बचत

करें और देश को मजबूत बनाएं।’ पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन की बचत करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और अनावश्यक सोने की खरीद से बचने की अपील की है। उनका मानना है कि अगर देशवासी थोड़ी सावधानी

बरतें, तो विदेशी मुद्रा पर दबाव कम होगा और भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत बन सकेगी। यही वजह है कि अब ‘सोना कम खरीदो, देश आगे बढ़ाओ’ का संदेश देशभर में चर्चा का विषय बन गया है।



अर्थशास्त्री क्यों मानते हैं सोना ‘गैर-जरूरी आयात’ ?

अर्थशास्त्रियों के अनुसार तेल रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन सोना जरूरी वस्तु नहीं माना जाता। बड़ी मात्रा में सोने का आयात देश के चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा सकता है। यही वजह है कि आर्थिक संकट के समय सरकारें सोने के आयात पर नजर रखती हैं।

पहले भी सरकारें उठा चुकी है ऐसा कदम

यह पहली बार नहीं है जब सोने के आयात को लेकर चिंता जताई गई हो। इससे पहले भी सरकारें गोल्ड इम्पोर्ट पर आयात शुल्क बढ़ा चुकी हैं। साथ ही गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों को बढ़ावा देकर लोगों को फिजिकल गोल्ड खरीदने से रोकने की कोशिश की गई है।

शादी-ब्याह में बढ़ती है सोने की मांग

भारत में शादी-ब्याह के दौरान सोने की खरीद परंपरा का हिस्सा मानी जाती है। हर साल देश सेकड़ों टन सोना आयात करता है। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, इसलिए इसकी मांग और बढ़ जाती है।

1967: इंदिरा गांधी ने की थी अपील

6 जून 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव था। भारत को अण्डाट रूप 20 साल से हुए थे और पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध से उच्च घुसक। उस समय भारत मौद्रिक सुखे का सामना कर रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग शून्य था।

1991: सोने ने दिवालिया होने से बचाया

केंद्रीय बैंक के पास मौजूद सोने ने देश को दिवालिया होने से भी बचाया है। बात 1991 की है। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। भारत के पास कच्चा तेल और उर्वरकों जैसी जरूरी चीजों के आयात का पेमेंट करने के लिए नुश्किले से 3 लाखों का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब भारत ने पहली बार केंद्रीय बैंक में रखे **■ शेष पृष्ठ 6 पर**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपील

पीएम मोदी रविवार को कहा था, ‘आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं।’

■ सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देशहित में लोगों को एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए।

■ पेट्रोल, गैस और डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है।

■ अनावश्यक वाहन उपयोग कम करें। मेट्रो में सफर और कारपुलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठकर ले जाएं।

■ देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए।

■ शायदियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देशहित में होगा।

■ हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी।

इन 4 मदों में ही इस साल 22 लाख करोड़ रुपए खर्च

सोने में सालाना 6 लाख करोड़ खर्च

भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024-26 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है।

विदेश यात्रा पर 3 लाख करोड़ उड़ा रहे

2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी भारतीयों ने विदेशों में खर्च बढ़ा दिया है। भारतीय मुद्रा का दूसरे मुद्रा में एक्सचेंज होना और विदेशों पर खर्च करने से रुपया लगातार कमजोर हुआ।

फर्टिलाइजर: 1.50 लाख करोड़ आयात

इस साल भारत ने विदेशों से 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है। इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं। सरकार जैविक खेती को बढ़ा रही है।

कच्चा तेल- 10 लाख करोड़ का आयात

भारत जरूरत का 70% तेल आयात करता है। इस पर 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ खर्च हुए। क्रुड के भाव घटने से 2025-26 में खर्च 10.35 लाख करोड़ रुपए था। पिछले दो महीने के युद्ध में क्रुड 50% महंगा हुआ है। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। युद्ध से क्रुड आयात लगातार महंगा हो रहा है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) की 2026 की पहली तिमाही (व्यू-1) की रिपोर्ट के अनुसार, रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद वैश्विक सोने की मांग 2% बढ़कर 1,231 टन तक पहुंच गई। मुख्य रूप से बार और कांइन में निवेश ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया, जबकि केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी मजबूत बनी रही। अप्रैल 2026 में गोल्ड ईटीएफ में भी 6.6 अरब डॉलर का निवेश वापस लौटा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु (व्यू-1- 2026)

मांग में बढ़ोतरी: पहली तिमाही में कुल मांग 1,231 टन रही, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी अधिक है।

निवेश में तेजी: सुरक्षित निवेश की मांग के कारण निवेशकों ने डिजिटल गोल्ड और सोने के बार/सिक्कों में भारी खरीदारी की।

केंद्रीय बैंक की खरीदारी: केंद्रीय बैंक लगातार सोना जमा कर रहे हैं।

कीमतों में रिकॉर्ड तेजी: रिकॉर्ड कीमतों के कारण ज्वेलरी की मांग पर दबाव बना रहा।

ईटीएफ में वापसी: अप्रैल में वैश्विक फिजिकल गोल्ड (ईटीएफ) में 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश फिर से शुरू हुआ, जिसमें भारत में भी 11 महीने से लगातार निवेश आ रहा है।

आज

बेबाक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है ताकि विदेशी मुद्रा बच सके। पीएम की इस अपील पर राष्ट्रीय भिखारी महासंघ ने घोषणा कर दी है कि वे सोना नहीं खरीदेंगे और विदेश भी नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा खुश तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं जिन्हें लिए पहले ही चुनावी घोषणाओं को अमलीजामा पहनाना टैढ़ी खीर है अब वे कम से कम एक साल तक तो शादी पर आठ ग्राम सोना और बच्चा होने पर सोने की अंगुठी देने के वादे से पल्ला झाड़ सकते हैं।

तापमान

अधिकतम 44° न्यूनतम 27°

बाजार भाव

गोल्ड
1,51,140

सिल्वर
2,54,798

शेयर बाजार

सेंसेक्स
77,328.19

निफ्टी
24,176.15

विश्व जनसंख्या भारत जनसंख्या

8,291,743,121

1,474,975,253

गरमा-गरम

रुपया बेहाल

गड़बड़ी : एनटीए ने माना- हम जिम्मेदार, सवाल पूछने पर बिना जवाब दिए निकले शिक्षा मंत्री प्रधान

नीट का पेपर लीक, परीक्षा रद्द सीबीआई को जांच का जिम्मा

नई दिल्ली/ए। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को नीट (यूजी) 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने कहा- इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, 6-8 दिन में नई तरीका का ऐलान होगा। उधर, केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले में मीडिया ने **■ शेष पृष्ठ 6 पर**

एक ही हैंडराइटिंग में लिखे 300+ सवाल, 150 परीक्षा में आए

‘प्रसन बैक’ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। इसमें से पहले किसी व्यक्ति को नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है। यानी 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे ‘वैश्वचन बैक’ से आए। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी विशेष वैश्वचन बैक से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहु आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती।

7 मई को एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी मिली: एनटीए डीजी

7 मई की रात हमें एक हिसलब्लोअर के जरिए जानकारी मिली थी कि परीक्षा होने से पहले किसी व्यक्ति को काटसॉफ्ट पर कुछ सवाल भेजे गए थे, जो परीक्षा के सवालों से मेल खा रहे थे। हमारी जिम्मेदारी थी कि इन आरोपों की जांच करें और यह पता लगाएं कि क्या ये पीडीएफ 3 मई यानी परीक्षा के दिन से पहले किसी के पास मौजूद थीं। जांच में पाया गया कि कुछ सवाल हमारे प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। यह भी सामने आया कि 1 और 2 मई को यह पीडीएफ कुछ लोगों के मोबाइल फोन में मौजूद थी।

मध्यप्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को हर समय तत्पर तैयार : सीएम यादव

मध्यप्रदेश को फ्रांस की ओर से प्राप्त होगा अधिकतम सहयोग = फ्रांस राजदूत माथू

मुख्यमंत्री निवास में फ्रांस के राजदूत और इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कान्क्लेव के प्रतिनिधियों का हुआ आत्मीय स्वागत

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से

प्रतिनिधियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से फ्रांस के राजदूत थियरी माथू ने भी भेंट की। फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि मध्यप्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस की ओर से अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश में आगामी वर्ष होने वाले ग्लोबल समिट की दृष्टि से फ्रांस और मध्यप्रदेश के मध्य दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाने के प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मुख्यमंत्री निवास में मंगलवार की शाम राउंड टेबल मीटिंग में कॉन्क्लेव में हुए विचार-विमर्श और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के संबंध में की गई पहल की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत में फ्रांसीसी राजदूत श्री माथू का अंगवस्त्र **■ शेष पृष्ठ 6 पर**

सीएम यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अपने कारकेड में घटाई वाहनों की संख्या

राष्ट्र हित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने पर मध्यप्रदेश में होगा अमल, निर्देश जारी

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आगामी आदेश तक अपने कारकेड में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री परिषद के सदस्यों से वर्तमान वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने सहित राष्ट्र हित में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की अपील की थी। मध्यप्रदेश गंभीरता से इस पर अमल करेगा। इस तारतम्य में राज्य सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आगामी आदेश तक

मुख्यमंत्री के कारकेड में 13 वाहनों के स्थान पर 8 वाहन ही चलेंगे। उनके भ्रमण के समय वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। सभी मंत्रीगण यात्रा में न्यूनतम वाहनों का प्रयोग करेंगे। यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि नव नियुक्त निगम-मंडल के पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करें और वाहन रैली आयोजित न करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान और दिए गए सुझावों के अनुरूप मध्यप्रदेश में शासकीय कार्यों में मितव्ययता के उपायों पर अमल करने को कहा है। मंत्रीगण सहित निगम-मंडल के पदाधिकारियों और आम नागरिकों से वाहनों के कम से कम प्रयोग करने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग न किए जाने को कहा गया है।

इस बार देश में मानसून 4-6 दिन पहले आने का अनुमान

■ यूपी-बिहार समेत 5 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

■ राजस्थान का बाड़मेर दूसरे दिन सबसे गर्म, पारा 47.3 डिग्री

दिल्ली/ए। देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर पहुंचने की संभावना है।

इधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में एक

न्यूज गैलरी

शासकीय भवनों में रेस्को मॉडल से सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूकता जरूरी : मंत्री शुक्ला



जिला पंचायत भोपाल में शासकीय संस्थाओं और रेस्कू विकासक इकाइयों के मध्य हुए विद्युत क्रय अनुबंध

भोपाल/नवप्रदेश। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निरंतर ईंधन (फ्यूल) और ऊर्जा बचाने का आह्वान किया गया है। हमें दृढ़ संकल्प के साथ इस उर्जों में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप शासन और प्रशासन को एक साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी की ओर झिपट होना होगा। मंत्री श्री शुक्ला मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में प्रदेश के विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों में सोलर स्पाट संयंत्र स्थापना के लिये शासकीय संस्थाओं व रेस्को विकासक इकाइयों के मध्य विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री शुक्ला ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि हमारी 50 प्रतिशत ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होनी चाहिए और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आमजनों में जागृकता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आने वाले समय में हर घर की छत पर सोलर पैनल नजर आने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि कि रेस्को पद्धति के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में समय पर भुगतान एवं उचित मेंटेंनेंस सुनिश्चित किया जाए। अगर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने कहा कि रेस्को योजना शुन्य निवेश, पहले दिन से बचत और नेट जीरो की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह शासन के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। उन्होंने कहा कि यह एक साझेदारी का प्रोजेक्ट है, इसलिए सभी संबंधित विभागों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। प्रबंध संचालक श्री अमनबीर सिंह बैस ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रेस्को पद्धति से 3.78 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली जनरेट होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्परता से बेहतर प्रबंध कर कार्य करने के निर्देश दिए। एमडी श्री बैस ने बताया कि बिजली बिलों का भुगतान 3 से 10 तारीख के बीच करने पर भुगतान राशि में 1 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, जबकि देरी से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की पेनेल्टी लगाई जाएगी। योजना के सफल एवं दृढ़तापूर्ण क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। शासकीय कार्यालय इस मॉडल को अपनाकर न केवल आर्थिक बचत करेगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना अहम योगदान देंगे। बैठक में कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती इला तिवारी एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

**फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैंबर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रदेश के विकास को नई
गति देने वाला प्रमुख स्तंभ : मंत्री पटेल**

भोपाल/नवप्रदेश। फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैवर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मध्यप्रदेश के विकास को नई गति देने वाला प्रमुख स्तंभ है। प्रदेश के स्थानीय और युवा उद्योगपतियों को नई दिशा दे रही। पंचायत और ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल निजी होटल में फेडरेशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में रोजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल प्रोव्हेस्टर सम्मिट के आयोजन और उद्योगों को दिए जा रहे नीतिगत इन्वेस्टमेंट्स प्रदेश के छोटे उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में एक नया आत्मविश्वास जागा है, जिससे अब गांव का व्यक्ति भी उद्योग लगाने का साहस जुटा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप भी समारोह में शामिल हुए और उन्होंने भी संबोधित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मजदूर और उद्योगपति के बीच का संबंध हितांतक टकराव की जगह आपसी समन्वय का होना चाहिए और इसे वास्तविकता में बदलना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में मंत्री श्री पटेल ने फेडरेशन प्रतಿನिधियों को श्रम संबंधी विभागियों समितियों में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने ५१% जैसी पहलों का उल्लेख किया, जो श्रम और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करने का कार्य कर रही हैं। मंत्री श्री पटेल ने उद्योगों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्किल मैपिंग पर विशेष बल दिया और उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे अपने आवश्यक ५%स्किल लेवल% की पहचान कर विभाग को सूचित करें। सरकार इन जरूरतों के आधार पर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर कुशल कार्यबल उपलब्ध कराएगी, जिससे उद्योगों को श्रमकों की कमी का सामना न करना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश कृषि उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर रहा है इसलिए अब हम सभी को प्रति प्रतिशत प्रतिशत स्थिति लाजिस्टिक्स और स्पलाई चैन के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही, उन्होंने श्रम विभाग में जारी सुधारों की चर्चा करते हुए बताया कि अनावश्यक कानूनों को समाप्त किया जा रहा है और शेष प्रमुख कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड और डिजिटल सिस्टम लागू किए गए हैं जिससे मध्यम और सिरटम आधारित और पारदर्शी बनी रही। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में वर्ष 2025 को ५%उद्योग वर्ष% के रूप में मनाया गया है जिसका मुख्य केंद्र स्थानीय उद्यमियों और युवाओं को नए अवसर प्रदान करना था। मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि फेडरेशन ने उद्योगपतियों के हित में शासन के कार्यों में निरंतर सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने उद्यमियों से गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखने का आग्रह किया, जिससे वैश्विक बाजार में प्रवेश की साख और मजबूत हो सके। मंत्री श्री काश्यप ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्वहण के बारे बताते हुए कहा कि विभाग ने पिछले डेढ़ वर्षों में 1200 से अधिक प्लॉट पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन आवंटित किए हैं और आगामी दो वर्षों में 3 हजार नए प्लॉट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश ने नियाता को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत लैंड-लॉकड राज्ज होने की चुनौतियों को देखते हुए नियातियों को 50 प्रतिशत परिदहन सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सब्सिडी वितरण की इस पूरी प्रक्रिया को ५%डेट ऑफ प्रोडक्शन% के आधार पर पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है, जिससे उद्यमियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि व्यापारियों के कल्याण के लिए एक ५%व्यापार बोर्ड% का गठन किया गया है, जिसमें फेडरेशन के प्रतिनिधि को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान

राजधानी

मध्यप्रदेश और फ्रांस का सहयोग औद्योगिक विकास, नवाचार और वैश्विक निवेश के नए अवसर तैयार करेगा : मंत्री काश्यप

फ्रांस और भारत के बीच दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी हो रही है लगातार मजबूत : फ्रांस राजदूत मथाउ

त्वरित निर्णय, पारदर्शिता और
तेज क्रियान्वयन की कार्य
संस्कृति : मुख्य सचिव जैन

मध्यप्रदेश में भारत-फ्रांस औद्योगिक साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार

उद्योग जगत के 150
प्रतिनिधियों ने की कॉन्क्लेव में
सहभागिता

भोपाल/नवप्रदेश। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि मध्यप्रदेश आज शांति, स्थिरता और औद्योगिक संभावनाओं का मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के

अनुरूप निवेशक-अनुकूल नीतियाँ विकसित की हैं, जिससे उद्योगों में लाभांशों में वृद्धि संभव है। सफलताक वित्तपोषण तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश के हृदय स्थल पर स्थित होने के कारण भारत के प्रमुख बाजारों तक सहज और संतुलित पहुँच प्रदान करता है, जिससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई नेटवर्क अत्यंत सुगम एवं किफायती बनता है। मंत्री श्री काश्यप ने यह भी कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में इंडो-फ्रेंच कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा। मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में मध्यप्रदेश तेजी से नई संभावनाएँ विकसित कर रहा है। सिंचाई क्षमता में हृद्य विस्तार से नई आधारित उद्योगों और खाद्य



प्रसंस्करण क्षेत्र को विशेष गति मिली है। मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि कारोबार सुगमता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने देश में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है तथा निवेशकों के लिए पारदर्शी और उद्योग समर्थक वातावरण तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस सहित यूरोपीय देशों के साथ मध्यप्रदेश औद्योगिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और ऐसे

आयोजन वैश्वक निवेश,
तकनीकी सहयोग और नवाचार
को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने
विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश
और फ्रांस के बीच यह सहयोग
आने वाले समय में और अधिक
सशक्त होगा तथा यह साझेदारी
औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन
और आर्थिक प्रगति के नए
अवसर तैयार करेगी।
भारत में फ्रांस के राजदूत श्री

थायरी मथाउ ने कहा कि इंडो-फ्रेंच-इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होतों आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने अपनी उद्योग अनुकूल नीतियों और निवेश समर्थक वातावरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए नई संभावनाएं निर्मित की हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत के बीच दृढ़ताकात्मक एवं भरोसेमंद साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है तथा दोनों देश आर्थिक सहयोग, नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 700 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां कार्यरत हैं, जो रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल,

कृषि, अधोसंरचना, रिटेल, जैव विविधता, शिक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में फ्रांस की कंपनियों मध्यप्रदेश के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के साथ फ्रांस के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में शिक्षा, पर्यटन, अकादमिक आदान-प्रदान और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग और अधिक विस्तारित होगा।

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश निवेश आधारित औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर रणनीतिक रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने बाबई औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद परियोजना पर कार्य प्रारंभ हुआ

समय-सीमा में कार्य करें पूर्ण

: प्रमुख सचिव डॉ. कुमार

31 कन्या छात्रावास बनेंगे
आदर्श, 15 मई से शुरू होगा
शौर्य संकल्प प्रशिक्षण

2 दिन में लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान, 15 जून से विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिए पूरे वर्ष कर सकेंगे आवेदन

भोपाल/नवप्रदेश। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा कर अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव डॉ. कुमार ने %शैक्षी संकल्प प्रशिक्षण योजना- 2026% की तैयारियों की

जानकारी ली। प्रमुख सचिव ने इसके प्रभावी और सुचारु क्रियान्वयन के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आलस्य और पिछड़ा वर्ग तथा मालसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर के नेतृत्व में योजनातर्गत 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य सैन्य बलों में भर्ती के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए समय-समय में कार्य कर अप्रार्थियों को सुगमतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है योग: मंत्री परमार

घर-घर योग, हर व्यक्ति
निरोग अभियान के अंतर्गत
प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण
एवं जन-जागरूकता
कार्यक्रम का किया शुभारंभ

भोपाल/नवपदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, राज्य सरकार योग को नए नए तर्क पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। -घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोगः अभियान का उद्देश्य, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना तथा स्वस्थ एवं निरोग समाज का निर्माण करना यह बात उच्च शिक्षा, एकांकीकृत शिक्षा एवं आयुष्य मंत्री श्री इन्द्र सिंह परमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के सहित आयोजन एवं व्यापक जनभागीदारी आयुष्य विभाग करने के उद्देश्य से आसुय विभाग द्वारा -घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोगः अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रदेशव्यापी योग प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कर कहा। यह अभियान 12 मह



से 21 जून 2026 तक प्रदेशभर में संचालित होगा। आयुष्मन् मंत्री श्री परमार ने कहा कि योग, भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण आधार है और वर्तमान समय में स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाने का सबसे प्रभावी माध्यम भी है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार योग एवं आयुष्मन् को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 'योग-मण्डि' एवं 'योग-दूत' तैयार किए जा रहे हैं, जो घर-घर जाकर नागरिकों को योग के प्रति प्रेरित करेंगे। साथ ही



विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तक भी इस अभियान का विस्तार किया जा रहा है, जिससे युवाओं में योग एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित की जा सके। श्री परमार ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को व्यापक जनभागीदारी एवं उत्साह के साथ मनाने की तैयारियों को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। संदेश में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग आज वैश्विक जनआंदोलन बन चुका है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ

जीवनशैली, मानसिक संतुलन एवं आंतरिक चेतना को जागृत करने का प्रभावी माध्यम है। डॉ. यादव ने कहा कि योग एवं आयुर्वेद भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं, जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही हैं। डॉ. यादव ने प्रदेश में आयुष सेवाओं को के विस्तार, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के सुदृढीकरण तथा योग एवं वेलनेस गतिविधियों को जनसामान्य तक पहुंचाने के प्रयासों को सराहना करते हुए अभियान की सफलता की आह्वान किया। प्रमुख सचिव आयुष श्री शोभित जैन ने बताया कि यह अभियान 21 जून तक निरंतर चलेगा, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग शिक्षक नागरिकों के छोटे-छोटे समूहों को नियमित योगाभ्यास कराएंगे। श्री शोभित जैन ने बताया कि अभियान के अंतर्गत राज्यभर के लगभग 2000 आयुष संस्थानों आयुष महाविद्यालयों, चिकित्सालयों एवं आयुष्मान

देश के गेहूं निर्यात में म.प्र. का योगदान 40 प्रतिशत

ओमान, यमन, यूएई, कतर, सउदी अरब में मध्यप्रदेश के गेहूँ की बड़ी साख

भोपाल/नवपद देश।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नवपद देश की नीतियों और योजनाओं के परिणामस्वरूप इस साल गेहूँ उत्पादन 365.11 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। उत्पादनका बढ़कर 3780 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है। मध्य प्रदेश गेहूँ प्रदेश बन गया है। देश के कुल गेहूँ उत्पादन में मध्यप्रदेश की योगदान 18 प्रतिशत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मध्यप्रदेश के गेहूँ की मांग लगातार बनी हुई है। प्राकृतिक मिटलस के कारण शरबती और डूंगरम गेहूँ की मांग जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, यूके, दुबई,



मध्यप्रदेश ने परंपरागत गेहूँ उत्पादक राज्यों की बराबरी कर ली है। वर्ष 2004: 05 में सिर्फ 42 लाख हैक्टेयर में गेहूँ होता था, जो आज बढ़कर 96.58 लाख हैक्टेयर हो गया है।



क्या है मध्यप्रदेश के गेंहूं में

भारत सरकार के गेंहूँ अनुसंधान निदेशालय ने अपने अनुसंधान में दो हजार सेम्पल का परीक्षण करने के बाद उच्च स्तर की गुणवत्ता का दावा पाया। प्रदेश

के सामान्य से सामान्य किस्म के गेहूँ में भी औसत रूप से 12.6 प्रतिशत प्रोटीन, 43.6 पीपीएम (पाईर से पर मिलियन) आयरन तथा 38.2 पीपीएम जिंक पाया गया है। कठिया प्रजाति के गेहूँ में भरपूर प्रोटीन, आयरन, मैनीज और जिंक है। इन्हीं विशेषताओं के मध्यप्रदेश के गेहूँ को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। प्रदेश में गेहूँ की उड़ाई जाने वाली किस्मों की अपनी विशेषताएं हैं, जैसे जे.डब्ल्यू.एस.17, जे.डब्ल्यू.3020 और जे.डब्ल्यू.321 नामक गेहूँ की किस्में - एक

सिंचाई में 35 क्रिंटल तक उत्पादन देती हैं। जे.डब्ल्यू. 1142, जे.डब्ल्यू. 3288 तथा जे.डब्ल्यू. 1203 किस्मों से अधिक तापमान में भी बेहतर उत्पादन मिलता है। जे.डब्ल्यू. 1202 और जे.डब्ल्यू. 3288 तथा जे.डब्ल्यू. 1106 किस्में प्रोटीन से भरपूर हैं। एमपीआर 1215 और जे.डब्ल्यू. 3211 किस्में निर्यात के लिये बेहतर हैं। पौष्टिक आहार बनाने के लिये गेहूँ वर्ष 2026 में की जो 5 किस्में उपयोग में आ रही हैं उनमें से 4 मध्यप्रदेश में विकसित की गई हैं।



विधायक मोहले बोले-योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

मुंगेली/नवप्रदेश। जनपद पंचायत मुंगेली अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल मैदान ग्राम चमारी में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और मौके पर ही समस्याओं के निराकरण का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुंगेली विधायक पुत्रूलाल मोहले अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक श्री मोहले द्वारा विभिन्न

विभागों के स्टॉलों के निरीक्षण से हुई। इसके बाद पूजा-अर्चना व दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। विधायक मोहले ने शासन की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम

व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने आमजनों को योजनाओं का लाभ उठाने प्रेरित करते हुए कहा कि खाद्य विभाग के द्वारा राशनकार्डधारकों का ई केवाईसी किया जा रहा है। सभी एक सप्ताह के भीतर ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करें, ताकि राशन नियमित रूप से मिले। आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृति किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जिले के ग्राम पलानसरी निवासी गुरुदयाल को भारतीय वन सेवा परीक्षा में 105वाँ रैंक



हासिल करने के लिए उनके परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विधायक श्री मोहले ने 01 करोड़ 14 लाख रूपए

दुल्लापुर और टेढ़ाधौरा शामिल हैं। इसके साथ ही कलस्टर के 30 ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए क्रमशः 06-06 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्रों के बन जाने से आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज ने बताया कि शिविर में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ भी वितरित किए गए। 20 हितग्राहियों को आवास की चाबी, 05 स्व सहायता

समूहों को चेक, 11 हितग्राहियों को केसीसी के तहत चेक, 10 हितग्राहियों को फ्लटदार पैधा, 15 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, वय वंदना कार्ड और आभा कार्ड, 10 हितग्राहियों को अरहर मिनी किट, 07 हितग्राहियों को नौनी सुरक्षा प्रमाण पत्र, 12 हितग्राहियों को श्रम कार्ड, बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही 05 बच्चों को निःशुल्क गणवेश का वितरण किया गया।

न्यूज गैलरी

1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लेगी ‘वीबी जीरामजी’ योजना

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अधिनियम 2025' को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की घोषणा की है। नए कानून के प्रभावी होते ही मनरेगा योजना समाप्त हो जाएगी। नई योजना का उद्देश्य केवल मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके तहत जल संरक्षण, आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन, जलवायु अनुकूल कार्य और स्थानीय संसाधनों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। नई व्यवस्था में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा में 100 दिन थी। रोजगार के लिए आवेदन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समय में काम न मिलने पर पात्र परिवारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी रखा गया है। सबसे बड़ा बदलाव भुगतान प्रक्रिया में है अब मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।भुगतान में 15 दिनों से अधिक देरी होने पर श्रमिकों को क्षतिपूर्ति राशि भी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत जल संरक्षण संरचनाएं, बाढ़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और अन्य ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' के जरिए ग्राम सभाओं की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य तय किए जाएंगे। इससे पंचायतों की भूमिका और मजबूत होगी। पूरी योजना को पीएम गतिशक्ति और जीआईएस आधारित डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे कार्यों की मॉनिटरिंग रियल टाइम में होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। निर्देशों के अनुसार मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत सभी कार्यों को 15 जून 2026 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। केवल पौधारोपण एवं नर्सरी संधारण कार्यों को जुलाई माह में भी जारी रखने को अनुमति दी गई है।

ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन व मक्का उत्पादन को अपना रहे किसान

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। जिले में श्फसल विविधीकरण’ के अंतर्गत किसान अब पारंपरिक धान की खेती छोड़कर लाभप्रद वैकल्पिक फसलों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। जिले के किसानों ने जल संरक्षण और बेहतर आय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर रागी, मूंगफली, उड़द, मूंग और मक्का जैसी फसलों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इस नई पहल से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, बल्कि गिरते भू-जल स्तर को रोकने में भी मदद मिल रही है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 634 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग के सतत मार्गदर्शन और जागरूकता प्रयासों के फलस्वरूप अब तक 209 हेक्टेयर भूमि पर वैकल्पिक फसलों की बुवाई सफलतापूर्वक की जा चुकी है। किसान अब धान के स्थान पर मुख्य रूप से उड़द, मूंग, मूंगफली, रागी और मक्का जैसी फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं डुबाने वाले क्षेत्रों में धान की बुवाई की जा रही है। फसल विविधीकरण की दिशा में जिले के किसान नई सोच और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर सफलता की मिसाल पेश कर रहे हैं। पारंपरिक खेती से हटकर वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ते कदम किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक आय दिला रहे हैं। क्षेत्र के कई प्रगतिशील किसान अब अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरे हैं। उदयपुर विकासखंड के ग्राम तोलंगा के किसान बनवारी ने इस वर्ष ग्ल की अधिक खपत वाली धान की खेती के स्थान पर उड़द की फसल को अपनाया है। उनका कहना है कि दलहन फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है तथा लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है। साथ ही बाजार में दलहन फसलों की अच्छी मांग होने से बेहतर मुनाफा प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि फसल परिवर्तन से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल रहा है।

अंबिकापुर में बाइक को अज्ञात-वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत

सरगुजा/नवप्रदेश। सरगुजा में नेशनल हाईवे-43 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार नाबालिग समेत 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों शहीद से लौट रहे थे। वहीं, एक और हादसे में नेशनल हाईवे-130 अंबिकापुर-बिलासपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर को चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक, लुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम सिलसिला निवासी विकास टोप्पो (17) गांव के ही विकेश एक्का के साथ बाइक से शहीद होने के लिए लमगांव गया था। दोनों रात करीब 9 बजे घर लौट रहे थे। लमगांव के खालपारा के पास नेशनल हाईवे-43 पर अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में बाइक सवारों की टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि, बाइक चला रहे विकेश एक्का की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक में पीछे बैठे विकास टोप्पो गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर पंकज पटेल ने उन्हें पहचान लिया और सूचना परिजन को दी। दोनों को तत्काल रघुनाथपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने विकेश को मृत घोषित कर दिया और विकास को अंबिकापुर रेफर कर दिया। विकास टोप्पो को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति के कारण तत्काल रायपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे रायपुर के बजाय मिशन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां कुछ देर में उसकी भी मौत हो गई। घटना की सूचना पर लुण्डा पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना के बाद वाहन का चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला था।

सेतगंगा क्षेत्र में जल्द शुरू होगा नवीन नहर निर्माण कार्य

मुंगेली/नवप्रदेश। सेतगंगा क्षेत्र में नवीन नहर निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ होगा। क्षेत्र के विधायक पुत्रूलाल मोहले व किसानों ने जिले की जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता से संयुक्त से बात की। संबंधित अधिकारी ने आश्वासन दिया कि नहर कार्य का प्रस्ताव पास हो चुका है। जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा।



क्षेत्रीय भारतीय किसान संगठन ने सेतगंगा क्षेत्र में नहर निर्माण के लिए प्रयासरत है। किसानों ने अनेकों बार जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर जनदर्शन और सम्बंधित अधिकारी को आवेदन दे चुके हैं। किसान संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सेतगंगा क्षेत्र में रबी और खरीफ फसल होती है पानी की कमी के कारण खेती प्रभावित होती है। समीपवर्ती जिले कवर्धा के

पंडरिया विकासखंड के अंतर्गत कुबा खुर्द में हाफ नदी पर कुबा डायवर्सन बांध क्षेत्र के प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है। यह डायवर्सन स्थानीय किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही पंडरिया के प्राकृतिक दृश्य में और अन्य जगह विकल्प है सेतगंगा क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कोई पक्की नहर या वितरक नाली उपलब्ध नहीं है नवीन नहर निर्माण से लगभग

40-50 गाँवों के किसानों की 25 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। किसानों का आय में डबल वृद्धि हो सकती है। इसी तारतम्य में गत दिवस विधायक पुत्रूलाल मोहले एवं किसान संघ के पदाधिकारी मनोहर यादव, संजय सिंह परिहार, रोहित सागर, दीनबन्धु चंद्राकर, नरेंद्र जायसवाल, कलेश्वर साहू, बीर सिंह व यशवंत गबेल किसानों के साथ मुंगेली-कवर्धा के अधिकारी की संयुक्त बैठक की गई। जिसमें

अवगत कराया गया कि बरसात के बाद तत्काल नहर खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। मुंगेली जिले के लगभग 25000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जाएगा। यह पानी से महका भूमियापारा, दुल्लापुर बीजातराई से लेकर के मुंगेली के पहले पंदवानी और सड़क के दायीं ओर इधर सुकली, लालपुर, केसली, माराडबरी, तलवारपुर से लेकर के आगे बांकी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हैं।

नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत आधारशिला : संगठन पदाधिकारी

गेवरा दीपका/नवप्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर दीपका डिस्पेंसरी एवं, नेहरू शताब्दी चिकित्सालय गेवरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीपका में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा नर्सिंग स्टाफ को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया तथा स्वास्थ्य सेवाओं में उनके समर्पण, सेवा भावना एवं महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई। हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य व्यवस्था

की आधारशिला है इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नर्स स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर मानव सेवा को नर सेवा नारायण सेवा के रूप में

मैनपाट के 64 लोगों को बेदखली का नोटिस

***स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, *सुनवाई का आश्वासन मिलने पर किया स्थगित**

सरगुजा/नवप्रदेश। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में प्रशासन ने 64 लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया है। रोपाखार इलाके में नोटिस मिलने के बाद कब्जाधारियों में हड़कप मच गया है। सोमवार को इस कार्रवाई के विरोध में नगरवासियों के साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बाद

में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का मौका देने की बात कही, जिसके बाद प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया।सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र के कमलेश्वरपुर में जिला प्रशासन ने 64 लोगों को नोटिस जारी किया है। रोपाखार और बाजार डांड इलाके में इन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है।बताया गया है कि किसी ने 2 से 5 डिगमिल जमीन पर मकान और दुकान बना ली है, जबकि कुछ लोगों ने जमीन को घेरकर भी कब्जा किया हुआ है।मैनपाट तहसीलदार न्यायालय

में अतिक्रमण के खिलाफ सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद नवंबर-दिसंबर 2025 में ही बेदखली का नोटिस जारी किया गया था। रोपाखार में लगभग 64 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। यहां 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कब्जा करना पाया गया है। तहसीलदार उमेश बाज द्वारा एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ 11 मई को बाजारडांड की मुख्य सड़क पर चक्काजाम व धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।

पेज 1 का शेष...

नीट का पेपर लीक...
सवाल पूछ तो वह बिना कुछ बोले निकल गए।
केरलम से सीकर पहुंचा प्रश्न बैंक, नीट का पेपर 'प्रश्न बैंक' के जरिए लीक किया गया। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे। ये सभी हाथ से लिखे गए और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही थी। जांच एजेंसी पता लगा रही है कि आखिर यह पेपर लीक कहां से हुआ। हालांकि, इसका खुलासा राजस्थान के सीकर से हुआ।
1 मई: केरलम से राजस्थान भेजा क्वेश्चन बैंक: केरलम के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे चूरू के एक लड़के ने 'क्वेश्चन बैंक' सीकर में अपने दोस्त को भेजा।
2 मई: राजस्थान में पेपर शेरार हुआ: दोस्त ने 'क्वेश्चन बैंक' सीकर के एक पीजी संचालक को दिया। उसने पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स को 'क्वेश्चन बैंक'

शेयर कर दिया। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट्स और करियर काउंसलर्स तक पहुंचा। इसी तरह बंटता चला गया।
3 मई: पीजी संचालक ने पुलिस में शिकायत की: परीक्षा होने के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने उडोगी नगर थाने और एनटीए को यह शिकायत दी थी कि एक कथित 'क्वेश्चन बैंक' बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है।
6-7 मई: पेपर से जुड़ी ऑनलाइन चैट वायरल: आंसर-की और परीक्षा से जुड़ी चर्चाएं ऑनलाइन सामने आने के बाद छात्रों और कोचिंग सेंटरों में एक कथित 'क्वेश्चन बैंक' को लेकर चर्चा शुरू हुई, जो कथित तौर पर असली परीक्षा से काफी मिलता-जुलता था।
7 मई: एनटीए ने गड़बड़ी की बात कही: एनटीए ने पुष्टि की कि उसे परीक्षा के 4 दिन बाद, यानी 7 मई को कथित गड़बड़ियों से जुड़े इनपुट मिले थे। एजेंसी ने बताया कि यह मामला राजस्थान और उत्तराखंड से सामने आया।
8 मई: एनटीए ने जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी।

10 मई: 13 लोग अरेस्ट: राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कहा कि उसने नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों से 13 लोगों को अरेस्ट किया।
इस बार देश में मानसून...
प्रदेश के 38 जिलों में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आंधी-तूफान और बारिश से 5 घंरों और 7 गोशालाओं की छतें उड़ गईं।
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हीटवेव जारी है। देश में सोमवार को राजस्थान का बाढ़मैर सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 47.3 डिग्री दर्ज किया गया। जैसलमेर में 46.5 डिग्री, फलोदी में 45.6 डिग्री और बीकानेर में 45.3 डिग्री तापमान रहा। मध्य प्रदेश के रतलाम में पारा 45 डिग्री के पार रहा।
1991: सोने ने दिवालिया होने
20 टन सोने को गिरवी रख 200 मिलियन डॉलर जुटाए थे।
कुछ समय बाद भारत ने बैंक ऑफ

इंग्लैंड को 47 टन सोना भेजा था। इस धनराशि से भारत को तत्काल बाहरी भुगतान दायित्वों को पूरा करने और दिवालियापन से बचने में मदद मिली।
मध्यप्रदेश उद्यमियों के साथ कदम
और पुष्प-गुच्छ से स्वागत करते हुए और विक्रमादित्य वैदिक घंटी भेंट की।
कॉन्क्लेव में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस कंपनियों और मध्यप्रदेश सरकार के बीच एक समझौता जापान सहित 8 अभिरूचि पत्र (लेटर ऑफ इंटेट) प्रस्तुत किए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फ्रांस से भोपाल पधारे सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि बदलते दौर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में फ्रांस ने भारत सरकार की नीतियों का स्वागत किया। भारत-फ्रांस की मित्रता के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह मैत्री पुनर्नी है और आगे भी परस्पर सहयोग की परम्परा बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने

कहा कि भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था। फ्रांस से भारत ने राफेल डील भी की। दुनिया का एडवांस फाइटर जेट राफेल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत सरकार ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। यह हमारी मित्रता के लिए सोने पर सुहागा है। इससे वैश्विक स्तर पर नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। भारत के साथ काम करते हुए सभी क्षेत्रों में व्यापार-व्यवसाय की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हम रक्षा, तकनीक, कौशल विकास सहित अन्य क्षेत्रों में मिलकर अच्छी नीतियों के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव नजर आए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद एक नया भारत देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी औद्योगिक निवेश की अपार क्षमता, योग्यता और संभावनाएं हैं।

खरीफ सीजन से पहले खाद-बीज का टोटा, किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

■ सोसायटियों में तालाबंदी जैसे हालात



खुले बाजार में लूट और नकली बीज का डर

किसान नेताओं का आरोप है कि सरकारी सोसायटियों में पर्याप्त स्टॉक न होने का फायदा निजी दुकानदार उठा रहे हैं। किसानों को मजबूरी में ऊंचे दामों पर खाद और बीज खरीदना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता नकली खाद और बीज की बिक्री को लेकर है, जिससे फसल बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। कंडेल क्षेत्र से उठी यह मांग अब पूरे जिले के किसानों की आवाज बन चुकी है।

सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराई जाए, तो त्रुण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों की शिकायतों के बीच धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि जिले में खाद का स्टॉक पर्याप्त है। लेकिन इसका वितरण एक वैज्ञानिक पद्धति के तहत किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। कलेक्टर ने रासायनिक खादों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए कहा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि किसान केवल रासायनिक खादों पर

निर्भर न रहें। प्रशासन जैविक खाद और गोबर कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे लंबे समय में किसानों को बेहतर उत्पादन मिलेगा। आगे क्या? किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सोसायटियों में खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो खरीफ की बुआई पिछड़ सकती है, जिसका सीधा असर जिले के कुल उत्पादन पर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किसानों की मांग पर कोटे में बढ़ोतरी करता है या नहीं।



थाईलैंड घूमने गए भारतीयों में से चार अचानक बेहोश, एक की मौत



फुकेट (थाईलैंड)। थाईलैंड के फुकेट से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां घूमने गए चार भारतीय नागरिक एक कैफे में भोजन के दौरान अचानक बेहोश हो गए। इस रहस्यमयी घटना में एक भारतीय पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य का अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि की है और आवश्यक जानकारी साझा की है। भारतीय दूतावास ने सोशल

मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, दूतावास थाई अधिकारियों के संपर्क में है और उस घटना पर करीब से नजर रख रहा है, जिसमें 9 मई 2026 को फुकेट में चार भारतीय पर्यटक बेहोश हो गए थे और बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दूतावास ने कहा कि उनमें से एक युवा भारतीय पर्यटक की मौत पर हमारी गहरी संवेदनाएं। दूतावास के अधिकारी इस दुख की घड़ी में हर तरह की मदद देने के लिए मृतक के परिवार के संपर्क में हैं। उनके पास से 2 लाख 95 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे और एक या दो वाहन भी जब्त किए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में छपरा जिले के मोहन राय के पुत्र अवधेश कुमार, मोतिहारी जिले के हिरालाल शाह के पुत्र पंकज कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अवधेश कुमार विम्स कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये सभी एक संगठित सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। इनके मोबाइल से नीट परीक्षा के कई फ़र्जी एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इसी मामले में आगे की कार्रवाई के दौरान सीतामढ़ी के एक डॉक्टर के बेटे हर्षराज और मुजफ्फरपुर के मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर

नीट पेपर लीक का बिहार कनेक्शन नालंदा के सॉल्वर गैंग से जुड़े तार

नई दिल्ली/ए। नीट परीक्षा रद्द होने से पूरे देश में हड़कंप मच गया है तो वहीं इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार इस पूरे केस के तार बिहार के नालंदा से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले नालंदा पुलिस ने पावापुरी मोड़ के पास सॉल्वर गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2 लाख 95 हजार रुपये नकद बरामद किए गए थे और एक या दो वाहन भी जब्त किए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में छपरा जिले के मोहन राय के पुत्र अवधेश कुमार, मोतिहारी जिले के हिरालाल शाह के पुत्र पंकज कुमार शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अवधेश कुमार विम्स कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये सभी एक संगठित सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। इनके मोबाइल से नीट परीक्षा के कई फ़र्जी एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इसी मामले में आगे की कार्रवाई के दौरान सीतामढ़ी के एक डॉक्टर के बेटे हर्षराज और मुजफ्फरपुर के मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर



नीट-यूजी-2026 एग्जाम क्यों हुआ रद्द?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' को उससे पहले मंगलवार को रद्द करने की घोषणा की और कहा कि यह परीक्षा अलग से अधिसूचित तिथियों पर पुनः आयोजित की जाएगी। उसने कहा कि परीक्षा से संबंधित अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय पारदर्शिता बनाए रखने और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को बरकरार रखने के हित में लिया गया है। उसने कहा, "केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एनटीए द्वारा तथ्यों को परखे जाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा की गई जांच संबंधी जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने तीन मई 2026 को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को भारत सरकार की मंजूरी से रद्द करने और परीक्षा को अलग से अधिसूचित तिथियों पर पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया है।"

जेल भेजा गया है। एजेंसी ने कहा कि प्राप्त सूचनाओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि 'वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं

50 से 60 लाख रुपये तक की डील

पूछताछ में आरोपियों ने अन्य कई लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। राजगौर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यह गैंग नीट परीक्षा में पास कराने के नाम पर 50 से 60 लाख रुपये तक की डील करता था और एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपये तक वसूलता था। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।

है।' उसने कहा, पुनः होने वाली परीक्षा की तिथियाँ और उनके लिए जारी किए जाने वाले प्रवेश पत्र की समय-सारणी अगले कुछ दिनों में एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से सूचित की जाएगी। एनटीए ने कहा कि सरकार ने परीक्षा से जुड़े आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है। उसने कहा, -एनटीए सीबीआई को पूरा सहयोग देगी और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता प्रदान करेगी।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलापति विजय की पार्टी



चेन्नई/ए। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय तिरुपत्तूर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है यहां हुआ बेहद करीबी मुकाबला। टीवीके के उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति ने डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन को सिर्फ एक वोट से हराया। इस नतीजे ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। चुनाव आयोग के अनुसार, श्रीनिवास सेतुपति को 83,365 वोट मिले, जबकि पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट हासिल हुए।

डीएमके उम्मीदवार ने दोबारा गिनती की उठाई ये मांग

इतने कम अंतर से हार के बाद डीएमके नेता ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ डाक मतपत्रों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। इसी वजह से उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती कराने की मांग की। इसके साथ ही पेरियाकरुप्पन ने अदालत से यह भी अपील की कि जब तक मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, तब तक श्रीनिवास सेतुपति को विधायक के तौर पर शपथ लेने और विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से रोका जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK ने मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें पार्टी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति पर रोक लगाई गई थी। श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में DMK मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा नतीजा घोषित किए जाने के बाद चुने गए विधायक को बिना मजबूत कारण के रोकना ठीक नहीं है।

‘सनातन धर्म खत्म होना चाहिए’, उदयनिधि के बयान से फिर छिड़ा बड़ा विवाद

चेन्नई/ए। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को सनातन धर्म को खत्म करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि यह लोगों को बांटता है। उन्होंने सितंबर 2023 में दिए गए अपने विवादित बयानों को दोहराया। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने पहले भाषण में, डीएमके नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष तमिल थाई वाङ्मय (तमिल प्रार्थना गीत) को दरकिनार करने की किसी भी कोशिश की इजाजत नहीं देगा।

उन्होंने सदन में अपने भाषण में कहा, 'सनातन धर्म, जो लोगों को बांटता है, उसे निश्चित रूप से खत्म कर देना चाहिए।' 2023 में उनके इसी तरह के बयानों पर



काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद नेता को हिंदू समर्थक संगठनों की आलोचना और अदालती मुकदमों का सामना करना पड़ा था। उदयनिधि हाल ही में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी एक खास शिकायत को उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य गीत को कार्यक्रमों के क्रम में

उसके पारंपरिक महत्व के बजाय तीसरे स्थान पर रख दिया गया था। विपक्ष के नेता ने कहा, '...आपकी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई ऐसी घटना एक गलती थी, और आपको इस विधानसभा में इसे दोबारा होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे।' उन्होंने आगे कहा कि न सिर्फ विधानसभा में, बल्कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम या तमिलनाडु में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में 'तमिल थाई वाङ्मय' को हमेशा पहला स्थान दिया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, 'मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस मामले में कभी कोई समझौता न हो। हमें अपने अधिकारों और

परंपराओं की रक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए।' उन्होंने दावा किया कि इस तरह के बदलाव से राज्य के लोगों में काफ़ी गुस्सा और हैरानी फैली है। उन्होंने सदन को 2023 की उस घटना की भी याद दिलाई, जब सत्ताधारी सरकार ने राज्यपाल द्वारा प्रोटोकॉल में बदलाव करने की कोशिशों का विरोध किया था। मौजूदा विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को परिभाषित करते हुए, विपक्ष के नेता ने द्रविड़ आंदोलन के दिग्गज और छत्तू के संस्थापक सी.एन. अन्नादुरई के विचारों का हवाला दिया। उन्होंने विपक्ष की तुलना किसी वाहन के ब्रेक या बैल की लगाम से की, जो सरकार को जनहित की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है।

नीट रद्द : केंद्र पर बरसे अरविंद केजरीवाल सरकार समझती है सिर्फ आंदोलन की भाषा

नई दिल्ली/ए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को 3 मई को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दिया। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया है। परीक्षा अब अलग से अधिसूचित तारीखों पर फिर से आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय पारदर्शिता बनाए रखने और राष्ट्रीय परीक्षा



प्रणाली में विश्वास को संरक्षित करने के हित में लिया गया है। एजेंसी ने कहा कि प्राप्त जानकारी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं था। वहीं, नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने के

फैसले पर विपक्ष सरकार पर हमलावार है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द किए जाने पर, केंद्र के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब हथियार परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। ऐसा चार बार हो चुका है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण है।

खाने-पीने की चीजों ने बिगाड़ा बजट अप्रैल में 3.48% पर पहुंची महंगाई दर

नई दिल्ली/ए। भारत में आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर हल्का झटका लगा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह बढ़कर 3.48 प्रतिशत पर पहुंच गई है।



इससे पिछले महीने यानी मार्च में यह आंकड़ा 3.4 प्रतिशत पर था। इस बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों, विशेषकर रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों की कीमतों में आया उछाल है। हालांकि, अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात यह है कि समग्र महंगाई दर अब भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के चार प्रतिशत के लक्ष्य के काफी नीचे है। अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लोगों के रसोई का

बजट मुख्य रूप से बिगड़ा है। इसमें शामिल हैं फल-सब्जियाँ, दालें, अनाज, और अन्य दैनिकीय वस्तुएं। अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा महंगाई पर्सनल केयर और विविध वस्तुओं की श्रेणी में देखी गई, जिसने 17.66 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की।

इसके विपरीत, ईंधन से जुड़ी कीमतों में नरमी के कारण ट्रांसपोर्ट से जुड़ी महंगाई दर -0.01 प्रतिशत पर लगभग सपाट रही, जिससे माल ढुलाई और यात्रा लागत में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। महंगाई दर में मामूली वृद्धि हुई है, फिर भी सरकार और आरबीआई के लिए स्थिति नियंत्रण में है। भारत ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2021 तक के पांच वर्षों के लिए अपनी खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य 4 प्रतिशत (2% से 6% के दायरे में) पर बरकरार रखा है।

गई है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। महंगाई कीमतों में नरमी के कारण ट्रांसपोर्ट से जुड़ी महंगाई दर -0.01 प्रतिशत पर लगभग सपाट रही, जिससे माल ढुलाई और यात्रा लागत में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। महंगाई दर में मामूली वृद्धि हुई है, फिर भी सरकार और आरबीआई के लिए स्थिति नियंत्रण में है। भारत ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2021 तक के पांच वर्षों के लिए अपनी खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य 4 प्रतिशत (2% से 6% के दायरे में) पर बरकरार रखा है।

टी20 विश्व कप-2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का ऐलान

नई दिल्ली/ए। महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का ऐलान हो गया है। 2023 में संन्यास ले चुकी 37 साल की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल को विश्व कप की टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका का यह फैसला चौंकाने वाला है। 15-सदस्यीय टीम की कप्तानी लौरा वोल्वार्ट करेगी। 113 टी20 मैचों में 123 विकेट ले चुकी इस्माइल नई गेंद से अपनी पुरानी जोड़ीदार मारिजेन कैप के साथ जुड़ीं। कैप बीमारी से उबरकर वापस कर रही हैं। पूर्व कप्तान डेन वैन नीकेर्क ने भी संन्यास से वापसी के बाद से नौ अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्हें भी टीम में चुना गया है। टीम की कप्तानी लौरा वोल्वार्ट करेगी। मुख्य नामों में ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, क्लो ट्रायोन और अयाबांगा खाका शामिल हैं। विस्फोटक



फिनिशर और पूर्व अंडर-19 कप्तान कायला रेंनेके अपना पहला टी20 विश्व कप खेलेंगी। विकेटकीपर बल्लेबाज कराबो मेसो को भी टीम में जगह मिली है। एनेके बॉश, जिन्होंने पिछले टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को फइनल तक पहुंचाया था, इस बार टीम में जगह नहीं बना पाई हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की एक प्रेस रिलीज में मुख्य कोच मंडला माशिम्बी ने कहा, -शबनीम जैसी खिलाड़ी का वापस आना टीम के लिए बहुत मायने रखता है। उनमें अभी भी दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने और टीम को कुछ खास

उपलब्धि दिलाने में मदद करने की कितनी ललक है। हमें मारिजेन, डेन और कराबो जैसी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किए जाने की भी खुशी है। विश्व कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 1 में शामिल है। इस रूप में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, और पाकिस्तान शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका 13 जून को मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम: लौरा वोल्वार्ट , ताजमिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्फसेन, शबनीम इस्माइल, सिनालो जाफ्टा , मारिजेन कैप, अयाबांगा खाका, सुने लुस, कराबो मेसो , नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेंनेके, टुमो सेखुखुने, क्लो ट्रायन और डेन वैन नीकेर्क।

लकड़बग्घा-2 को 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा

मुंबई। अभिनेता और निर्देशक अंशुमन झा की फिल्म 'लकड़बग्घा 2 द मंकी बिजनेस' इस साल 79वें कान फिल्म फेस्टिवल के मार्च दु फिल्म (Marche du Film) में सोशल स्क्रीनिंग के लिए तैयार है। फिल्म 'लकड़बग्घा 2' साल के आखिर में रिलीज से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है। 'लकड़बग्घा 2 द मंकी बिजनेस' को 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। 'लकड़बग्घा 2' भारत और इंडोनेशिया के बीच पहला आधिकारिक सह-निर्माण (को-प्रोडक्शन) है। इस फिल्म का निर्देशन अंशुमन झा ने किया है। फिल्म में सनी पैग, डैन चुपोंग (हट्टुद-ब्रुह्म), आदिल हुसैन, सुने लुस, कराबो मेसो , नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेंनेके, टुमो सेखुखुने, क्लो ट्रायन और डेन वैन नीकेर्क।



Productions की जेनिफर पैंगल ने बताया कि उन्होंने 2023 में स्टेटगार्ट फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म 'लकड़बग्घा' देखी थी, जहां उसे 'झुझझुझु' 2, झुझझु' मिला था। तब से वे इस श्रृंखला पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'दुनिया में जानवरों के लिए लड़ने वाले हीरो की कमी है। भारत ने भी अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मार्शल आर्ट्स स्टार नहीं दिया है। यह फिल्म इन दोनों कमियों को पूरा करती है।' जेनिफर ने अंशुमन झा की तारीफ करते हुए कहा कि सारा-जेन डाक्स और अंशुमन झा ने भी अभिनय किया है। जर्मनी की कंपनी Webfilmland

